

प्रेषक,
मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 27 जनवरी, 2009

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-1/35/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2008-09 के लिए स्नातक एवं परास्नातक स्तरीय तकनीकी एवं व्यवसायिक कौर्स हेतु मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100प्रतिशत केन्द्र सहायतित) दिये जाने हेतु रु0. 2,40,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 "आयोजनागत" पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से रु0. 2,40,000.00 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 267/ XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च 2008 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवयवबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं समयान्तर्गत उपयोजिता प्रमाण पत्र, शासन एवं भारत सरकार को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किया जाये।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तपुरितका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकरिमिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत

शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 "आयोजनागत" शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

4. वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अबचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय।
6. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
9. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाएं-01 -अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति के मानक मद (100प्रतिशत केन्द्र सहायतित) 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।
11. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या:-645(P)/XXVII(3)/08-09 दिनांक 15 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या ७७ (1)/XVII(1)-3/08-07(45) 2007, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, नडवाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी-नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या: 1/35/2008/पीपी-1, दिनांक 15.12.2008 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से


(आर० के० चौहान)
अनु सचिव।